







# संपादकीय

## ओं के खिलाफ र राष्ट्र की चिंता

**सर्वसुलभ इंसाफ की उम्मीद को पंख लगे...**

लौलेत गगे

सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयन्ती के अवसर पर सभी ने शीघ्र न्याय की जरूरत को स्वीकारते हुए कहा कि 'तारीख पे तारीख' की संस्कृति से तौबा करने का वक्त आ गया है? न्याय प्रणाली की कमियों को दूर करने के रास्ते उद्घाटित होने ही चाहिए। यह सुखद, अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक अवसर ही है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 75 साल का गरिमामय सफर पूरा कर लिया है। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के प्रयासों में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को यादगार बनाने के लिये बाकायदा डाक टिकट व सिक्के भी हाल ही में जारी किये गए और विभिन्न आयोजनों में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को अधिक सशक्त बनाने के विषय पर गंभीर मंथन भी हुआ, ऐसे ही आयोजनों में राष्ट्रपति द्वापदी मुर्मूँ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड ने इस बात पर बल दिया कि समय पर न्याय मिलने से ही न्याय का वास्तविक लक्ष्य पूरा होता है। 'न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत से विमुखता है' वाली इस बात को सभी महसूस करते हैं लेकिन न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर आसीन मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की इस स्वीकाररिकि के गहरे निहितार्थ हैं। 'न्याय प्राप्त करना और इसे समय से प्राप्त करना किसी भी राज्य व्यवस्था के व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है।' सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयन्ती के अवसर पर सभी ने शीघ्र न्याय की जरूरत को स्वीकारते हुए कहा कि 'तारीख पे तारीख' की संस्कृति से तौबा करने का वक्त आ गया है? न्याय प्रणाली की कमियों को दूर करने के रास्ते उद्घाटित होने ही चाहिए। यही वजह है कि जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समाप्त समारोह में राष्ट्रपति द्वापदी मुर्मूँ ने जो कुछ कहा, उसे देश की पूरी न्याय व्यवस्था के लिए अलार्म बेल माना जा सकता है। राष्ट्रपति ने याद दिलाया कि जब तक न्यायपालिका देश के आम लोगों को सहजता से इंसाफ तक पहुंचने का रास्ता मुहैया नहीं करती, तब तक उसका काम पूरा नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिये अदालतों में स्थगन की संस्कृति को बदलने के प्रयास करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने

A composite image showing two men in traditional Indian attire (dhotis and blouses) holding framed certificates. The man on the left is smiling and looking towards the camera. The man on the right has a white beard and is also smiling. Both certificates feature a blue and gold design with the Indian emblem at the top.

से न्याय पाने की प्रक्रिया बड़ी खर्चीली है और इसमें बेहिसाब वक्त लगता है। इन दोनों ही का नतीजा इसी रूप में सामने आता है कि इंसाफ की आस लेकर अदालत पहुंचा व्यक्ति फैसला आने तक टूट चुका होता है। इसीलिये राष्ट्रपति ने ठीक ही कहा कि किसी गंभीर अपराध से जुड़े मामले का फैसला आने में 32 साल लग जाए तो लोगों को ऐसा लगना अस्वाभाविक नहीं कि शायद अदालतें ऐसे मामलों को लेकर संवेदनशील नहीं हैं। राष्ट्रपति ने किसी खास मामले का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका इशारा अजमेर में पॉक्सो अदालत द्वारा इसी 20 अगस्त को सुनाए गए फैसले की तरफ था। एक चर्चित सेक्स स्कैंडल से जुड़े इस मामले में छह लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाने में 32 साल लग गए। यह अपनी तरह का कोई इकलौता मामला नहीं है। बेहद गंभीर और वीभत्स अपराध के सैकड़ों ऐसे मामले हैं, जो अदालतों में बरसों से लंबित पड़े हैं। लोग अदालतों में मुकदमों के लंबे खिंचने से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि किसी तरह समझौता करके पिंड छुड़ाना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयन्ती पर महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि न्यायपालिका और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या करने जा रहा है, जिससे लोग न्याय प्रक्रिया से हताश-निराश होकर समझौता करने के लिए बाध्य न हों? प्रश्न यह भी है उहें समय पर त्वरित न्याय कब मिल सकेगा? दुर्भाग्य से ये प्रश्न दशकों से अनुतरित है। इससे पहले जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों

में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर बल दिया था ताकि महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ सके निस्संदेह, हाल के वर्षों में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे हमारे समाजशास्त्री और कानून लागू करवाने वाली विभिन्न एजेंसियां भी हैरान-परेशान हैं। कोलकाता में एक मेडिकल कालेज के अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुरुर्क्ष व हत्या कांड ने पूरे देश को उद्गेलित किया है पूरे देश में अपराधियों को शीघ्र व सख्त दंड देने की मांग की जा रही है। यदि पुलिस व जांच एजेंसियां पुख्ता सबूतों के साथ अदालत में पहुंचें तो गंभीर मामलों में आरोप जल्दी सिद्ध हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है। ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। भारत के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर विश्वास किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष ‘मदर ऑफ डेमोक्रेसी’ के रूप में भारत के गौरव को और बढ़ाते हैं। आजादी के अनुत्काल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है विकसित भारत, नया भारत बनने का। नया भारत, यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत। हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तम्भ है। भारत में लोकतंत्र और उदारवादी मूल्यों के मजबूत करने में न्यायपालिका ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। संविधान का रखवाला, गरीबों के

आलेख

# मुस्लिम बीएलओ को हटाया गया जाना क्यों और क्या

अजय दीक्षित

रहता है तो उस तकाल निलाबत कर दिया जाता है बिना कारण जान। किसी के घर में कोई गम्भीर हादसा हो गया, कोई बीमार पड़ गया, कोई आपदा आ गई, इसकी जानकारी नहीं ली जाती है। हम बात बी.एल.ओ. की कर रहे थे। ज्यादातर इसमें सरकारी शिक्षकों को लगाया गया है। उन्हें शायद कुछ पारिश्रमिक मिलता है, परन्तु वे शायद ही कभी किसी वोटर को कहते होंगे कि किसे वोट दें। ज्यादातर बी.एल.ओ. महिलाएं हैं। उनके पति उनके स्थान पर काम करते हैं। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं और शिक्षक शिक्षकाओं को वोटर के घर-घर जाने का काम सौंपते हैं। ज्यादातर बी.एल.ओ. इससे मुक्त चाहते हैं। असल में 4 जून के परिणाम के बाद भाजपा में हलचल है। उसका 370 का नारा और 400 पार का नारा सफल नहीं हुआ। अब केन्द्र में भाजपा की सरकार न होकर एन.डी.ए. की सरकार है। उत्तरप्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। योगी जी के खिलाफ उसके ही दो उपमुख्यमंत्री रहे हैं। अब आर.एस.एस. के निर्देश पर जरूर ऊपरी तौर पर समझौता हो गया लगता है और केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि योगी जी देश के सबसे कुशल मुख्यमंत्री हैं। चर्चा यह भी है कि शाह और योगी जी में 36 का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधायिकी को लेकर उपचुनाव है। इसमें एक-एक सीट पर योगी जी ने 30-30 मंत्रियों को उतार दिया है। अब मुस्लिम बी.एल.ओ. को हटाकर शायद दिवा स्वप्न देखा जा रहा है कि सभी 10 सीटें बीजेपी जीत जायेगी। असल में उत्तरप्रदेश में इन 10 सीटों के लिए सपा और कांग्रेस में समझौता हो गया है जो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। सुकून की बात यह है कि विपक्ष के बीट यायवती की बहुजन समाज पार्टी काटेगी। इससे भाजपा को ज्यादा फायदा होगा। मुस्लिम बी.एल.ओ. तो खुश ही होंगे कि उन्हें इस कार्य से मुक्त मिल गई। असल में कोई भी बी.एल.ओ. यह काम करना नहीं चाहता और इससे छुटकारा चाहता है। हमारे राजनेता महलों में रहकर दिन में सपने देखते हैं अच्छा हो उन्हें ज़मीनी हकीकत मालम हो।

**भाजपा**  
हरिशंकर व्यास

निर्भाई। वे ऐसे ही अध्यक्ष बने हुए हैं। यही हाल सभी प्रदेश कमेटियों का है। हर जगह प्रदेश कमेटियां सिर्फ हैं, उनको कोई काम नहीं करना है। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां भी भाजपा ने उनको किनारे ही करके रखा है। जम्मू कश्मीर में भाजपा का पूरा संगठन ही शिथिल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पसंद से राम माधव को कश्मीर घाटी की राजनीति संभालने के लिए भेजा है। चार साल पहले पार्टी महासचिव पद से हटा कर उन्हे बियाबान में भटकने के लिए छोड़ दिया गया था। वे भाजपा और संघ दोनों से बाहर थे। हालांकि परदे के पीछे से वे प्रधानमंत्री के लिए विदेश मामलों में कुछ काम करते थे लेकिन राजनीतिक भूमिका नहीं बची थी। उन्होंने चूंकि कश्मीर घाटी की पार्टियों खास कर पीड़ीपी के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं और सज्जाद लोन या अल्ताफ बुखारी जैसे नेताओं के साथ भी कामकाजी रिश्ते हैं तो उनको वहां की राजनीति संभालने के लिए भेजा गया है। जम्मू की राजनीति पहले जितेंद्र सिंह कर रहे थे लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में लंबे समय तक रहे उनके भाई देवेंद्र सिंह को भाजपा में शामिल कराया गया है। सोचें, वे उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक सलाहकार थे। उनके जिम्मे जम्मू की राजनीति हैं। भाजपा के अपने पुराने चेहरे गायब हैं। पूर्व मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कविंद्र गुप्ता दोनों की टिकट की ओषणा नहीं हुई है। भाजपा ने पहले जी किशन रेड़ी को वहां का प्रभारी बनाया था लेकिन अब

रेहुई को राम माधव के साथ काम करना है। इसी तरह हरियाणा में भाजपा ने पिछले 10 साल से गैर जाट की राजनीति की है और इसी वजह से उसको सफलता भी मिली लेकिन चुनाव से ऐसे पहले उसने कांग्रेस की किरण चौधरी को पार्टी में शामिल कराया और राज्यसभा भेज दिया। दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सांसद बनने से खाली हुई राज्यसभा सीट पर किरण चौधरी उच्च सदन में गई हैं। अब किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ प्रचार कर रहे हैं। सोचें, हरियाणा में भाजपा के तमाम पुराने नेता रामबिलास शर्मा, अनिल विज, ओमप्रकाश धनखड़, कैट्टेन अभिमन्यु आदि हाशिए में हैं और परिवारवाद के कथित विरोधी नरेंद्र मोदी की पार्टी में हरियाणा के तीनों लालों के परिवार के सदस्य राजनीति कर रहे हैं। देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला बंशीलाल की बहू किरण चौधरी व पोती श्रुति चौधरी और भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई, बहू रेणुका बिश्नोई और पोते भव्य बिश्नोई भाजपा की राजनीति के चेहरे हैं। झारखंड में भाजपा की राजनीति अब पूर्ण तरह से हिंमत बिस्व सरमा के हाथ में है। वहाँ बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी विश्वनाथ प्रदेश के संगठन प्रभारी हैं और शिवाराज सिंह चौहान चुनाव प्रभारी हैं लेकिन भाजपा को चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव के सह प्रभारी हिंमत बस्वा सरमा। पार्टी में किसको शामिल किया जाए, किसको नहीं शामिल किया जाए, किसको टिकट दी जाएगी, किसको कह

# महिला विरोधी अपराध के दलदल में भद्रलोक

उमेश चतुर्वेदी

अभी बहुत दिन नहीं हुआ, जब पश्चिम बंगाल के सदेशखाली से भी महिलाओं से बलात्कार की खबरें सामने आई थीं। वहाँ की घटना की जब परतें खुलने लगीं तो पता चला कि रेप की घटनाएं अपराध और राजनीति के नापाक गठजोड़ का नतीजा हैं। बंकिम चंद्र की शस्य श्यामला माटी वाला पश्चिम बंगाल शक्ति पूजक समाज है। शरद ऋतु के स्वागत के साथ बंगाल की धरती दुर्गा के स्वागत में हर साल विभोर होती रही है। बंगाल में महिलाओं का सम्मान कैसी परंपरा है, इसे समझने के लिए दुर्गा पूजा के विधान को समझना चाहिए। जहाँ मूर्ति बनाने के लिए उन वेश्याओं के घर से पहली मिट्टी लाई जाती है, जिन्हें आम तौर पर समाज त्याज्य और गंदा मानता है। बंगाल की धरती कैसी नारी पूजक रही है, किस तरह वह नारियों का सम्मान करती रही है, इसके उदाहरण आजादी के आंदोलन के इतिहास में जैसे मिलते हैं, अन्य राज्यों में कम। स्वाधीनता संग्राम में जिन तीन महिलाओं ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया और अपने ज्ञान और संघर्ष से भारत को आलोकित किया, वे तीनों बंगाल की बेटियां थीं। पहली थीं अरुणा गांगुली, जो बाद में अरुणा आसफ़ अली बनीं। दूसरी थीं

सुचेता मजूमदार जो बाद में सुचेता कृपलानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तीसरी थीं सरोजिनी चट्टोपाध्याय जो बाद में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू बनीं। बंगाल की माटी नारी की कितना सम्मान करती रही है, उसका एक और उदाहरण कमला देवी चट्टोपाध्याय भी रहीं। जब भारत के अन्य इलाकों की महिलाएं घूंघट के पीछे सिर्फ परिवार के कोल्हू में पिस रहीं थीं, तब बंगाल ने अपनी बेटियों को वाजिब सम्मान दिया और उन्हें आगे बढ़ाया। उस बंगाल में कभी महिलाओं के साथ बदसलूकी की कल्पना तक नहीं की जाती थी। वहां अब हालात कैसे बदल गए हैं, इसका अंदाजा लगाने के लिए राधागोविंद कर अस्पताल में हुई घटना को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। समूचा देश अपनी आजादी की 77 वीं सालगिरह के जश्न में थककर पद्धत अगस्त की रात जब मीठी नींद के आगोश में था, भद्रलोक की राजधानी कोलकाता के राधा गोविंद कर यानी आरजी कर अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की बर्बरता पूर्वक रेप के बाद हत्या कर दी गई। बंगाल में देर रात तक दफ्तर से लौटने वाली लड़कियों की कभी घरवाले चिंता तक नहीं करते थे, अब वे परेशान हो उठे हैं। बंगाल के लोग अपनी बच्चियों के लिए चिंतित हो उठे हैं। बंगाल की धरती पर



शायद यह पहली ऐसी घटना है, जिसमें किसी महिला के साथ ऐसी बर्बरता की गई है। इससे शक्तिपूजक बंगाली समाज का क्रोध और क्षोभ से भरना स्वाभाविक है। दिलचस्प यह है कि पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है, जिसे महिला मुख्यमंत्री का गौरव हासिल है। महिला के राज में किसी महिला के साथ ऐसा दुराचार लोगों के गले आसानी से नहीं उतर रहा। इसलिए बंगाल इन दिनों खौल रहा है। बंगाल के चुनिंदा बुद्धिजीवियों को छोड़ दें तो समूचा बौद्धिक समाज सड़कों पर उतर आया है। जो चुप हैं या व्यवस्था की तरफदारी कर रहे हैं, वे सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं, सांसद या किसी अन्य पद पर हैं। अभी बहुत दिन नहीं हआ। जब पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से भी महिलाओं से बलात्कार की खबर सामने आई थीं। वहाँ की घटना की जपरते खुलने लगीं तो पता चला कि रेप व घटनाएं अपराध और राजनीति के नापां गठजोड़ का नतीजा हैं। संदेशखाली व लेकर बंगाली समाज में उबाल तो आय लेकिन वैसा नहीं, जैसा आरजी व अस्पताल की दुराचार के बाद दिख रहा है। शायद संदेशखाली की पीड़िताएं ग्रामीण इलाकों की हैं, जबकि आरजी कर व घटना उस कोलकाता शहर की है, जिस भद्रलोक समाज के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल की कड़वी सच्चाई बांगलादेश से हो रही अवैध घुसपैठ। अवैध घुसपैठिलों के समर्थन में बीजेपी छोड़ तकरीबन समूचे बंगाली राजनीति है। 34 साल के बामपं

शासन के दौरान इस घुसपैठ को वैधता मिली। वामपंथी शासन व्यवस्था के दौरान पार्टी केंद्र के नाम पर बड़ा झुंड उभरा। सरकार पर संगठन का नियंत्रण होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन संगठन की ओर से समानांतर व्यवस्था चलाना और शासन में हर स्तर पर हस्तक्षेप शासन की निष्पक्षता को तो खत्म करता ही है, शासन को पंगु भी बना देता है। प्रांत से लेकर ब्लॉक स्तर तक स्थापित वामपंथी व्यवस्था ने ऊपर से नीचे तक प्रशासन को अपना गुलाम बनाने में कामयाब रहा। प्रशासन और समानांतर पार्टी व्यवस्था ने मिलकर अपराध और राजनीति का मजबूत गठजोड़ बनाया। इस गठजोड़ में पैसा था, पॉवर था, ताकत थी। नीचे से मिले पैसे ऊपर तक पहुंचते रहे। जनता ठीं जाती रही है। पश्चिम बंगाल का समाज उस संस्थानिक व्यवस्था से इतना परेशान था कि संघर्षशील ममता बनर्जी में नई उम्मीद दिखी। बंगाली समाज को लगा कि संघर्षशील ममता नई बयार बनकर पश्चिम बंगाल की व्यवस्था में जमी काई को साफ कर देगी। उन्हें उम्मीद थी कि ममता अपने राजनीतिक औजारों से बंगाल की व्यवस्था में जमे नासूर को साफ कर देंगी। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। ममता भी उसी कदम पर चल पड़ी।





### व्यापार समाचार

#### एयरटेल ने कई आकर्षक लाभों के साथ सीमित अवधि के लिए फेस्टिव ऑफर्स लॉन्च किया

नई दिल्ली: आगामी त्योहारों के जश्न में, भारत के अग्रणी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में से एक, भारतीय एयरटेल (एयरटेल) ने आज अपने प्रीपेड प्राहकों के लिए विशेष ऑफर्स लॉन्च किए। यह ऑफर 6 सिंतंबर 2024 से 11 सिंतंबर 2024 तक केवल 6 दिनों के लिए वैध है, सीमित अवधि का सफरिटेल ऑफर्स ग्राहकों के लिए तैयार किये गए यह 3 विशेष पैक रु. 979, रु. 1029 और रु. 3599 पर कई लाभ देता है। यह पैक वॉयस, डेटा और ओटोटो स्ट्रीमिंग सेवाओं के विशेष लाभों से भरे हुए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है।

#### आईसीआरए ने वेदांता की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करते हुए किया ए

आईसीआरए ने वेदांता लिमिटेड की वीथावधि क्रेडिट रेटिंग को [ICRA] AA- से बढ़ाकर [ICRA] कर दिया है, जो कंपनी की मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल को दर्शाता है। अल्पकाल में सुधार से पैदा हुए पूर्ण रूप से एक विशेष लाभांश शामिल है। पिछली कुछ तिमाहियों में, वेदांता ने अपनी बैलेस शीट को डीलीवरेज किया है, जिसके परिणामस्वरूप वितर वर्ष 24 की पहली तिमाही में शुद्ध रुपये में दीवारीटाईडी अनुपात में 1.9% से वर्तमान में 1.5% तक सुधार हुआ है। वेदांता लिमिटेड अपने बकाया बैंड के एक बड़े हिस्से को पुनर्वित करने के लिए भी सक्रिय रूप से प्रयास करता है, जिसमें सुख्ख रूप से विशेष लाभांश शामिल हैं। सभी डीलीवरेजिंग प्रयासों से समूह की फर्मेन्सिश्यल फ्लेक्सिबिलिटी में भी समग्र रूप से सुधार होने की उम्मीद है।

#### शाओमी इंडिया ने कैरीना कैफको अपना ब्रांड एम्बेसेडर बनाया: स्मार्ट भविष्य के लिए फिर से नया गठबंधन

नई दिल्ली: अपने इनोवेशन के लिए मशहूर, ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्रांड, शाओमी इंडिया ने आज कैरीना कैफको अपना ब्रांड एम्बेसेडर घोषित किया। ब्रांड एम्बेसेडर के रूप में कैरीना कैफशाओमी के स्टारफेन, टीवी, और टेलीविजन का प्रमोशन करेगी। शाओमी का भारत में दस साल पूरे हो रहे हैं और इस साथ किया गया यह गठबंधन हर किसी तक अपने इनोवेशन पर्याप्त होने की शाओमी की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। इस गठबंधन में कैरीना की वैश्विक अवधि और आकर्षक सुदरता सिमटी हुई है। कैरीना कैफको स्पष्ट बाह्यिक अधिनियम अपने बैंड के एक बड़े हिस्से को पुनर्वित करने के लिए भी सक्रिय रूप से प्रयास करता है, जिसका लाभ समेकित इकाई की व्याज लागत को और कम करना है। सभी डीलीवरेजिंग प्रयासों से समूह की फर्मेन्सिश्यल फ्लेक्सिबिलिटी में भी समग्र रूप से सुधार होने की उम्मीद है।

#### ओला इलेक्ट्रिक ने फेस्टिव सीजन अपने एस1 पोर्टफोलियो पर 28,000 रुपये तक की आकर्षक डील्स और बेनेफिट्स के साथ शुरू किया

रायपुर: ओला इलेक्ट्रिक ने आज फेस्टिव सीजन से वहाने आकर्षक डील और ऑफर पेश किए। ग्राहकों को चुनिंदा एस1 स्कर्टर खरीदने पर 5,000 रुपये का डिकॉडर दिया जा रहा है। इसके अलावा, एक्सेसरीज और चुनिंदा बैंक के क्रेडिट कार्ड ईम्पार्टी पर कंपनी ने 11,000 रुपये तक की अतिरिक्त लाभ की घोषणा भी की है। ग्राहकों को 12,000 रुपये तक का एक्सेसरी बोनस भी दिया जा रहा है। इस आपक का लाभ ग्राहक नजदीकी आल इलेक्ट्रिक स्टोर पर आकर ले सकते हैं। यह ऑफर चुनिंदा शहरों में 15 सिंतंबर तक लागू रहेगा। कंपनी अपने उत्पादों की संपूर्ण श्रृंखला पर बोनस अतिरिक्त लागत के साथ 8,000 किलोमीटर की एक्सेंडेंड बैटरी वॉर्टी प्रयोग करती है। ओला इलेक्ट्रिक का मानवांश है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को उत्तम बढ़ी, और इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में आने वाली एक बड़ी बाधा दूर हो सकेगी। ग्राहक एड-ऑन वॉर्टी लेकर 1,00,000 किलोमीटर तक की दूरी को केवल 4,999 रुपये देकर और 1,25,000 किलोमीटर तक की दूरी को केवल 12,999 रुपये देकर वारंटी के अंतर्गत ला सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने एक 3 किलोवाट की पोर्टेबल फार्म चार्जर एक्सेसरी भी पेश की है, जो 29,999 रुपये में खरीदी जा सकती है। ओला इलेक्ट्रिक एक विशाल एस1 पोर्टफोलियो पेश करता है, जिसमें आकर्षक मूल्य में छ: उत्पाद हैं, जो विभिन्न रेंज की जरूरत वाले ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। कंपनी के प्रीमियम एस1 प्रो और एस1 एयर का मूल्य क्रमशः 1,34,999 रुपये और 1,07,499 रुपये हैं। वहीं मास-सेमेंट के स्कूटरों, एस1 एक्स+ और एस1 एक्स पोर्टफोलियो (2 किलोवाटबैटरी, 3 किलोवाटबैटरी, और 4 किलोवाटबैटरी) का मूल्य क्रमशः 89,999 रुपये; 74,999 रुपये; 87,999 रुपये और 101,999 रुपये हैं।

## मॉरीशस के साथ गोलरहित झ़ से आगे बढ़ना है लक्ष्य : मनोलो मार्क्वेज



हैदराबाद (एजेंसी)। फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में मनोलो मार्क्वेज के जीवन की शुरुआत भूलने योग्य रही जब भारत ने इंटरकॉटिनेंटल कप के वहाने में फीफा रैंकिंग में 179वें स्थान पर काबिज बत यह है कि विशेष लाभों के साथ गोलरहित झ़ से आगे बढ़ना नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि मॉरीशस के खिलाफ गोल बनाने वाली नींव है। सबसे अच्छी बात यह है कि विशेष लाभों के साथ गोलरहित झ़ से आगे बढ़ना है।

खिलाड़ियों के रवैये की आलोचना नहीं कर सकता,

जिन्होंने 100 प्रतिशत दिया। हमें केवल दो प्रश्नक्रिया स्तर पर कर सकते हैं, जो बाह्यिक यह कोई बहाना नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि मॉरीशस के खिलाफ गोल बनाने वाली नींव है। सबसे अच्छी बात यह है कि विशेष लाभों के साथ गोलरहित झ़ से आगे बढ़ना है।

खिलाड़ियों के रवैये की आलोचना नहीं कर सकता,

जिन्होंने 100 प्रतिशत दिया। हमें केवल दो प्रश्नक्रिया स्तर पर कर सकते हैं, जो बाह्यिक यह कोई बहाना नहीं है।

खिलाड़ियों के रवैये की आलोचना नहीं कर सकता,

जिन्होंने 100 प्रतिशत दिया। हमें केवल दो प्रश्नक्रिया स्तर पर कर सकते हैं, जो बाह्यिक यह कोई बहाना नहीं है।

खिलाड़ियों के रवैये की आलोचना नहीं कर सकता,

जिन्होंने 100 प्रतिशत दिया। हमें केवल दो प्रश्नक्रिया स्तर पर कर सकते हैं, जो बाह्यिक यह कोई बहाना नहीं है।

खिलाड़ियों के रवैये की आलोचना नहीं कर सकता,

जिन्होंने 100 प्रतिशत दिया। हमें केवल दो प्रश्नक्रिया स्तर पर कर सकते हैं, जो बाह्यिक यह कोई बहाना नहीं है।

खिलाड़ियों के रवैये की आलोचना नहीं कर सकता,

जिन्होंने 100 प्रतिशत दिया। हमें केवल दो प्रश्नक्रिया स्तर पर कर सकते हैं, जो बाह्यिक यह कोई बहाना नहीं है।

खिलाड़ियों के रवैये की आलोचना नहीं कर सकता,

जिन्होंने 100 प्रतिशत दिया। हमें केवल दो प्रश्नक्रिया स्तर पर कर सकते हैं, जो बाह्यिक यह कोई बहाना नहीं है।

खिलाड़ियों के रवैये की आलोचना नहीं कर सकता,

जिन्होंने 100 प्रतिशत दिया। हमें केवल दो प्रश्नक्रिया स्तर पर कर सकते हैं, जो बाह्यिक यह कोई बहाना नहीं है।

खिलाड़ियों के रवैये की आलोचना नहीं कर सकता,

जिन्होंने 100 प्रतिशत दिया। हमें केवल दो प्रश्नक्रिया स्तर पर कर सकते हैं, जो बाह्यिक यह कोई बहाना नहीं है।

खिलाड़ियों के रवैये की आलोचना नहीं कर सकता,

जिन्होंने 100 प्रतिशत दिया। हमें केवल दो प्रश्नक्रिया स्तर पर कर सकते हैं, जो बाह्यिक यह कोई बहाना नहीं है।

खिलाड़ियों के रवैये की आलोचना नहीं कर सकता,

जिन्होंने 100 प्रतिशत दिया। हमें केवल दो प्रश्नक्रिया स्तर पर कर सकते हैं, जो बाह्यिक यह कोई बहाना नहीं है।

खिलाड़ियों के रवैये की आलोचना नहीं कर सकता,

जिन्होंने 100 प्रतिशत दिया। हमें केवल दो प्रश्नक्रिया स्तर पर कर सकते हैं, जो बाह्यिक यह कोई बहाना नहीं है।

खिलाड़ियों के रवैये की आलोचना नहीं कर सकता,

जिन्होंने 100 प्रतिशत दिया। हमें केवल दो प्रश्नक्रिया स्तर पर कर सकते हैं, जो बाह्यिक यह कोई बहाना नहीं है।

खिलाड़ियों के रवैये की आलोचना नहीं कर सकता,

जिन्होंने 100 प्रतिशत दिया। हमें केवल दो प्रश्नक्रिया स्तर पर कर सकते हैं, जो बाह्यिक यह कोई बहाना नहीं है।

खिलाड़ियों के रवैये की आलोचना नहीं कर सकता,

जिन्होंने 100 प्रतिशत दिया। हमें केवल दो प्रश्नक्रिया स्तर पर कर सकते हैं, जो बाह्यिक यह कोई बहाना नहीं है।

खिलाड़ियों के रवैये की आलोचना नहीं कर

